RAJYA SABHA

Monday, the 22nd July, 1996/31st Asadha, 1918 (Saka)

The House met at eleven of the clock [Mr. Chairman *in the Chair.*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Supply of Controlled Ration Articles to Uttar Pradesh

*161. SHRIMATI MALTI SHARMA:†
SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that controlled ration articles viz. wheat, rice, sugar, kerosene oil, etc. supplied to Uttar Pradesh, particularly, the hill districts are untimely, inadequate and of inferior quality;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what steps are proposed to be taken to streamline the uninterrupted flow of controlled items to the said State in future?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गेहूं, चावल चीनी तथा मिट्टी के तेल के मासिक आवंटन आमतौर पर समय से प्राप्त हो जाते हैं। हाल के वर्षों में उठान बहुत कम रहा है, जिसका मुख्य कारण खुले बाजार में उनका आसानी से उपलब्ध होना है। जून, 1996 से उठान में सुधार हो गया है। भारतीय खाद्य निगम से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया है कि उन के बेस गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध रहे। राज्य सरकार ने फील्ड कर्मचारियों को सख्त अनुदेश दिए हैं कि वे केवल अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न उठाएं। राज्य को आवंटित किए जा रहे खाद्यान्न के पर्याप्त न होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश को अन्य सभी राज्यों की तरह चीनी का आवंटन 425 ग्राम प्रति-यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से किया जाता है। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश अधिकतम चीनी प्राप्त करता है। उत्तर प्रदेश को मिट्टी के तेल का आवंटन अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समान भूतकालिक आधार पर अर्थात गत समय के अनुसार किया जा रहा है।

श्रीमती मालती शर्मा: माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा है, जहां तक पहाड़ी लोगों का संबंध है, पहाड़ पर गेहूं, चावल, चीनी और खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बात थी, कि आम तौर पर ये सब चीजें पिछले दिनों खुले बाजार में सभी उपभोक्ताओं को मुहैया हो जाती थी, जिसके कारण लोगों ने राशन की दुकानों से सामग्री नहीं उठाई। महोदय, मैं यह जानकारी करना चाहती हूं माननीय मंत्री जी से कि खुले बाजार में और राशन की दुकानों की सामग्री की कीमत का अंतर क्या है? अगर उनकी कीमत खुले बाजार में भी उतनी ही है, तब तो उन्होंने वहां से उठा ली, कोई बात नहीं, लेकिन माननीय मंत्री जी मुझे इस बात की जानकारी दें कि खुले बाजार में चीजों की कीमत क्या है - गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि, जो राशन की दुकानों से चीजें मिलती हैं? सभापति महोदय, राशन की दुकान इसलिए खोली गई है ताकि गरीब जनता को कम कीमत पर चीजें उपलब्ध हो सकें लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह माना है कि क्योंकि खुले बाजार में ये सब चीजें मिल जाती हैं इसलिए आम तौर पर लोगों ने वहां से खरीदीं और राशन की दुकानों की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मैं माननीय मंत्री जी से एक तो चीजों की कीमतों के बारे में यह जानकारी करना चाहती हूं, क्योंकि सस्ते गल्ले की दुकानों पर लोग नहीं आए उन्होंने खुले बाजार में चीजें खरीद लीं, तो मंत्री जी कृपया बताएं कि राशन की दुकानों में चीजों की कीमतों में और खुले बाजार में चीजों की कीमतों में क्या अंतर है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, यह जो खुली दुकान है इसमें अभी, जहां का सवाल, सवाल है उत्तरांचल का, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का। इसमें

†The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Malti Sharma.

4.50 रुपए प्रति किलो गेहूं पी०डी०एस० में, क्योंकि माननीय सदस्या ने जानकारी चाही है कि वहां किस दर पर सामान मिल रहा है, और आर०पी०डी०एस० योजना के तहत, सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 3.77 रुपए प्रति किलो गेहूं का भाव है। क्योंकि दोनों सिस्टम वहां है, जो बिल्कुल हिली एरिया है वहां आर०पी०डी०एस० है और जो पहाड़ के ऊपर है, वहां पी०डी०एस०, जो जनरल सम्पूर्ण राज्य में लागू है पी०डी०एस० सिस्टम, उसके तहत दिया जाता है। तो कॉमन चावल है 6.00 रुपए प्रति किलोग्राम और सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, आर०पी०डी०एस० उसमें है 5.12 रुपए प्रति किलोग्राम। यह कॉमन चावल और गेहूं की बात मैंने आपको बताई है।

अभी माननीय सदस्या ने सवाल किया कि खुले बाजार में, जब वहां पर सामान इतना उपलब्ध है, जिसकी मैं जानकारी दे देना चाहता हूं, काफी स्टॉक हमारा भरा पड़ा है, जो आपने बताया ये लगभग 12 जिले, जो आपके पहाड़ी इलाके के जिले हैं........

वहां हम पी०डी०एस० और आर०पी०डी०एस० के माध्यम से आपूर्ति कर रहे हैं। उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वे हैं—हरवला, पिथौरागढ़, गंगाघाट, यमुनाघाट, सिमली और चमोली। नॉन हिली एरियाज़ हैं—भदोही और पदरौना। पूरे उत्तरांचल में जून के लिए जो ऐलॉटमेंट किया गया, वह मैं बता देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। जून, 1996 में उत्तरांचल के लिए 7102 मीट्रिक टन गेहूं का ऐलोकेशन किया गया।

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): मंत्री जी ने सवाल को बहुत दूर तक फैला दिया है। बुनियादी बात यह है कि खुले बाजार में कीमत क्या है और राशन की दुकानों पर जो आप देते हैं, उसकी कीमत क्या है? पहाड़ में रहने वाले लोगों को सस्ता मिल रहा है या नहीं, यह बताइए। ये कहां चले गए?

†[شری سکندر بخت: منتری جی نے سوال کو بہت دور تک پھیلا دیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کھلے بازار میں قیمت کیا ہے اور راشن کی دوکانوں پر جو آپ دیتے ہیں اسکی قیمت کیا ہے۔ پہاڑ میں رہنے والے لوگوں کو سستا مل رہا ہے یا نہیں یہ بتائیے۔ یہ کہاں چلے گئے۔]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः पहाड़ में रहने वाले लोगों को आर०पी०डी०एस० सिस्टम के तहत अनाज मिल रहा है और कम कीमत पर मिल रहा है।

श्री सिकन्दर बख्तः कम कीमत पर मिल रहा है तो ठीक है।

†[شری سکندر بخت: کم قیمت پر مل رہا ہے تو ٹھیک ہے۔]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः मैंने बताया है कि पहाड़ी इलाकों में कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्रीमती मालती शर्माः मान्यवर, व्यापारी जो अपना माल बेचेगा उसमें अपना मार्जिन तो रखेगा ही और आपकी राशन की दुकानें सरकारी हैं, इन दोनों में एक से दामों पर चीजें कैसे उपलब्ध हो सकती हैं? आपने राशन की दुकानों के लिए यह कह दिया कि वहां इनकी इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि वहां पहले ही खुले बाजार में लोगों को बड़ी आसानी से सामग्री उन्हीं दामों पर मिल जाती है। महोदय, बाजार में जो व्यापारी बैठा हुआ है वह गेहूं भी बेच रहा है, चीनी भी बेच रहा है और चावल भी बेच रहा है। वह, अपना सामान नीचे से लेकर जाता है और आप भी जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि ऊपर तक सामान ले जाने में कितना ढुलाई का खर्चा देना पड़ता है। तो व्यापारी की दर और आपके सामान की दर में कोई अंतर नहीं है, इसलिए लोग खुले बाजार में खरीद रहे हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मंत्री महोदय कृपया इसे स्पष्ट करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः मैंने पहले ही बताया कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां कम दाम पर सामान मिलता है ....(व्यवधान)

श्री महेश्वर सिंहः सभापति महोदय, प्रश्न बड़ा स्पष्ट है। माननीय सदस्या जानना चाहती हैं कि जो व्यापारी लोग सामान बेचते हैं उसकी कीमत क्या है और जो आपकी कंट्रोल रेट की दुकानें हैं, उनकी दरें क्या हैं? आपका कहना यह है कि वहां खुले बाजार में सस्ता सामान उपलब्ध है इसलिए वहां राशन नहीं मिलता,

†[ ] Transliteration in Arabic Script

क्या यह मानकर चलें हम? तो बताइए कि दोनों में क्या डिफरेंस है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अभी मैंने जिक्र किया है कि आर॰पी॰डी॰एस॰ के तहत पहाड़ी इलाकों में सबसे कम दाम पर सामान मुहैया कराया जा रहा है।

श्री महेश्वर सिंह: व्यापारी किस रेट से बेचता है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: किसी स्पैसिफिक सामान के बारे में पूछिए तो हम बता देंगे।

श्रीमती मालती शर्मा: आप राशन की दुकानों पर चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल, ये सब चीजें उपलब्ध कराते हैं। इन सबकी दरें बताइए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: चीनी का दाम पी॰डी॰एस॰ में 9.05 रुपए प्रति किलो है जब कि खुले बाजार में इसका दाम 14-15 रुपए प्रति किलो है।

श्रीमती मालती शर्मा: आपकी राशन की दुकानें वहां सामग्री उपलब्ध नहीं करा पातीं। वहां की जनता को आए दिन उत्तराखंड की मांग को लेकर आंदोलन करना पड़ता है और उसकी वजह से उनकी तनख्वाहें बंद हो जाती हैं और दूसरी ओर उनको महंगे दामों पर आवश्यक वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं। यह दोहरी मार उन पर पड़ती है। यह कहां का न्याय है? मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप राशन की दुकानों पर नियमित रूप से सामग्री उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैंने पहले ही आपको कहा, मैं डिटेल बता रहा था कि स्टॉक की पोजिशन क्या है। अभी तक हमने जो एलोकेशन किया है उसमें आफ-टेक कितना हुआ है। सामानों का जो आफ-टेक हुआ है वह सफिसिएंट है।...(व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त: पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को राशन महंगा मिल रहा है। क्यों महंगा मिल रहा है, सवाल इतना है।

†[شری سکندر بخت: پہاڑوں پر رہنے والے لوگوں کو راشن مہنگا مل رہا ہے - کیوں مہنگا مل رہا ہے سوال اتنا ہے -]

†[ ] Transliteration in Arabic Script

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महंगा नहीं मिल रहा है। यह बिल्कुल गलत जानकारी है।

श्री सिकन्दर बख्त: 14 रुपए बताया आपने 9 रुपए के मुकाबले।

†[شری سکندر بخت: ۱۴ روپیہ بتایا آپنے ۹ روپیہ کے مقابلے -]

श्री सिकन्दर बख्त: यह मैंने खुले बाजार का बताया है। सभापति महोदय, इसको क्लिअर कर लिया जाए। मैंने कहा कि खुले बाजार में 14 रुपए 60 पैसे में मिलता है। पी॰डी॰एस॰ में 9 रुपए 05 पैसे प्रति किलो है।

श्री सिकन्दर बख्त: पहाड़ में कितना मिल रहा है?

†[شری سکندر بخت: پہاڑ میں کتنا مل رہا ہے -]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जो हम राज्य सरकार को देते हैं वह 9 रुपए 05 पैसे किलो पी॰डी॰एस॰ में देते हैं।

श्री सिकन्दर बख्त: पी॰डी॰एस॰ नहीं है पहाड़ों में।

†[شری سکندر بخت: پی ڈی ایس نہیں پہاڑوں میں -]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: पहाड़ों में जो आर॰पी॰डी॰एस॰ है उसमें पी॰डी॰एस॰ से एक रुपया कम मिलता है। मतलब, 8 रुपए में मिलता होगा। 8 रुपए ही दाम होता है। एक रुपया कम होता है। जो पी॰डी॰एस॰ का दाम होता है उससे एक रुपया कम में आर॰पी॰डी॰एस॰ में दिया जाता है। इसलिए 8 रुपए प्रतिकिलो वहां मिलता होगा। जो राज्य सरकारें वितरित करती हैं, राज्य सरकारें हमारी एजेंसी हैं। सामान का दाम पूरे देश में एक तरह का होता है। एक मानक है केन्द्र सरकार का, चाहे पी॰डी॰एस॰ का हो, चाहे आर॰पी॰डी॰एस॰ का हो। इसलिए हम एक मानक से देते हैं।

अभी आप बता रही थी कि वहां सामान कम है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तरांचल में केवल तीन महीने की जो माननीय सदस्या की शंका है उसको मैं स्वीकार करता हूं, केवल तीन महीने के लिए जब वहां

एजीटेशन था, जब वहां उत्तराखंड के लिए आंदोलन चल रहा था उस समय जून के महीने में स्टॉक हो गया और प्रोक्योरमेंट भी अनाज का हुआ। हमको जो पोजिशन मिली है वह यह है कि वहां कुछ कम हुआ था। उत्तरांचल में 53.12 प्रतिशत हमारा व्हीट मिला था, जबकि पूरे होल यू०पी० में 60.89 था, जबकि अन्य महीनों में सभी जगह आर०पी०डी०एस० में ज्यादा उठान भी हुआ है, ज्यादा लिफ्टिंग भी हुआ है अनाज का। उसकी हम फिगर्स भी दे सकते हैं। अभी दूसरे महीने का ले लीजिए। पूरे उत्तरांचल में मई में 7102 मैट्रिक टन गेहूं का एलौटमेंट हुआ था जिस एलौटमेंट के अगेंस्ट वहां 5381 टन का उठान हुआ। यह गेहूं का हुआ और उसमें व्हीट इश्यू हुआ 4006, 4048 मैट्रिक टन।

श्रीमती मालती शर्मा: मान्यवर, उठान तो होगा।....(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please, this is not a discussion. Everybody wants to put questions. This is not fair.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, में आर०पी०डी०एस० का भी बतलाना चाहता हूं। उत्तरांचल में आर०पी०डी०एस० में 17324 मैट्रिक टन का एलौटमेंट हुआ था। इसमें 14925 मैट्रिक टन का उठान हुआ। इसमें लिफ्टिंग कितना अच्छा है पूरे उत्तरांचल के आर०पी०डी०एस० सिस्टम में। उत्तर प्रदेश में जो जनरल पूल है उसमें 29205 मैट्रिक टन का एलौटमेंट हुआ और उठान 16222 मैट्रिक टन का हुआ। इस प्रकार उठान भी पूरे उत्तर प्रदेश में कम है। जो आर०पी०डी०एस० का इलाका उत्तर प्रदेश में है उसमें ज्यादा उठान है। उसी तरह से राइस का है और अन्य सामानों का है हमारा राइस का 1,33,843 मैट्रिक टन का स्टाक है, जो पिछले तीन-चार महीनों से वहां पड़ा हुआ है। जो गोदाम की स्थिति है, जो सरकार की नीति है, हम आर०पी०डी०एस० योजना के तहत ज्यादा गोदाम हिल इलाकों में जो हिली रूरल एरिया है, निग्लेक्टेड इलाका है ऐसे इलाकों में हम कुछ नए गोदाम भी बना रहे हैं। हमारा जो गोदाम बनाने का प्रस्ताव है, उसकी मैं जानकारी दे देना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्या की जो शंका है कि इस वजह से अनाज नहीं पहुंच पाता है। पहले वाले गोदामों को छोड़कर जो हमारा प्रस्ताव है, वह रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट देहरादून में दस हजार मैट्रिक टन का जो स्टाक स्थित है उसके लिए जमीन का एक्विजिशन हो गया है। वह चालू होने ही वाला है। दूसरे अल्मोड़ा में रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट जहां हमारा स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, you can answer the rest while replying to others.

श्रीमती मालती शर्मा: सर, मेरा दूसरा प्रश्न भी है।

MR. CHAIRMAN: He has given a lot of information. The second questioner can put his question...(*Interruptions*) Your second supplementary is over, isn't it?

श्रीमती मालती शर्मा: सर, मैंने एक प्रश्न पूछा है। मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी रह गया है। मैं केवल इतनी जानकारी और चाहती हूं कि राशन की दुकान पर 425 ग्राम प्रति यूनिट चीनी देने का नियम है, तो मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूं कि पहाड़ का इलाका वैसे ही ठंडा होता है, वहां लोग चाय अधिक पीते हैं। तो क्या मंत्री महोदय इस कोटे को बढ़ा कर पूरे प्रान्त में प्रति यूनिट जो चीनी देते हैं, उसको बढ़ाने का कष्ट करेंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जहां तक कोटा बढ़ाने का सवाल है, 425 ग्राम प्रति यूनिट एक मानक बनाया गया है केन्द्र सरकार की ओर से। राज्य सरकार को चीनी और मिट्टी तेल का ऐलोकेशन एक बार किया जाता है। उनको पूरा अधिकार है, यदि वे बढ़ाना चाहें तो बढ़ाएं, केन्द्र सरकार इसके लिए तैयार है। यदि राज्य सरकार हिली इलाके में इसको बढ़ाना चाहे तो उनको पूरी आज़ादी है। हम तो एक साथ पूरे स्टेट का ऐलोकेशन कर देते हैं खास कर मिट्टी का तेल और चीनी में।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: राष्ट्रपति को कहिए, राष्ट्रपति महोदय का शासन है वहां पर।

MR. CHAIRMAN: You have put your questions...(*Interruptions*) You have put all your questions.

श्री राजनाथ सिंह: मान्यवर, क्वालिटी ऐनश्योर करने के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय मॉनीटरिंग सिस्टम जो है इस सरकार का क्वालिटी ऐनश्योर करने के बारे में वह पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। तो इस मॉनीटरिंग सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या सरकार के पास कोई कार्य-योजना है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता ज़ाहिर की है कि ग्रामीण इलाकों में कम चीनी देने का जो नियम है और जो अर्बन इलाका

है, शहरी इलाका है, वहां ज्यादा है, तो मैंने तो पहले ही ज़िक्र किया कि इसे मैं आप जैसे माननीय सदस्यों का और राज्य सरकारों का सहयोग चाहूंगा। अभी दिल्ली में 825 ग्राम प्रति यूनिट चीनी दी जाती है। मैं चाहता हूं कि आप यदि सहयोग करें तो हम इसको बदलने के लिए इस पर पूरी गंभीरता से विचार करेंगे।

श्री राजनाथ सिंह: किस प्रकार का सहयोग? ...(**व्यवधान**)...सभापति महोदय, मुझे संरक्षण चाहिए आपका। मंत्री जी हमसे किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं? वे हमारे दल के द्वारा किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं? साथ ही मान्यवर, मंत्री जी ने मेरे आरम्भ के दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। मान्यवर, मैं अपने विचारों का आपके द्वारा संरक्षण चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: You answer the specific questions.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं माननीय महोदय को स्पैसेफिक जवाब दे रहा हूं। माननीय सदस्य जिस दल से आते हैं, उस दल की सरकार दिल्ली में है।

श्री सतीश अग्रवाल: उससे क्या लेना-देना है?

SHRI SIKANDER BAKHT: Mr. Chairman, Sir, if you are satisfied with his reply, we have no objection.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, सरकार इस डिस्पैरिटी को खत्म करना चाहती है, सरकार का ऐसा विचार है किन्तु राज्य सरकारों का सहयोग लेना जरूरी है। पी॰डी॰एस॰ सिस्टम में दो धुरियां हैं, एक राज्य सरकार है एवं एक केन्द्र सरकार है। इसमें केन्द्र सरकार को राज्य सरकार का सहयोग प्राप्त होना बहुत जरूरी है क्योंकि पी॰डी॰एस॰ के ऐलोकेशन में जो असमानता है, उसको ठीक करने को, सुदृढ़ करने को केन्द्र सरकार अहमियत देती है। इस असमानता को दूर करने के लिए राज्य सरकारों का सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए यदि आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस डिस्पैरिटी को दूर करेंगे।

श्री राजनाथ सिंह: मान्यवर, मंत्री जी बार-बार दिल्ली सरकार की बात करके हमारे प्रश्न को टालना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए और मंत्री जी तैयार होकर सदन में उत्तर देने के लिए आएं।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री राजनाथ सिंह: मान्यवर, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। महोदय, मैं संरक्षण चाहता हूं। मेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

श्री रामगोपाल यादव: माननीय सदस्य ने जितना सवाल पूछा था, उससे अधिक जवाब मंत्री जी ने दे दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजनाथ सिंह: मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जानकारी प्राप्त करना हमारा प्रीविलेज है, यह हमारा अधिकार है।

SHRI SOM PAL: Sir, the issue which Mr. Raj Nath Singh has raised is of fundamental importance to the rural people...*(interruptions)*...

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: You are not the Minister. You please sit down...*(interruptions)*...

श्री अनंतराय देवशंकर दवे: आप मिनिस्टर नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)....

MR. CHAIRMAN: Mr. Som Pal, please sit down.

SHRI SOM PAL: Sir, this issue is of fundamental importance to the rural people. It is a fundamental Constitutional right of the rural people.

MR. CHAIRMAN: No. No fundamental rights are to be discussed now. Shri Brahmakumar Bhatt...*(interruptions)*...I have called another Member.

SHRI SOM PAL: The Government must take a decision on this.

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Mr. Chairman, Sir, is the hon. Minister aware ...*(interruptions)*...

श्री राजनाथ सिंह: महोदय, मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। हमारे किसी प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है।

MR. CHAIRMAN: Mr. Singh, will you please sit down? I will go to the next question. Please sit down. You had enough opportunity to put questions.

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Sir, is the hon. Minister aware that the

material which is given to the fair price shops...*(interruptions)*...

श्री राजनाथ सिंह: मान्यवर, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए और मंत्री जी इस प्रश्न की तैयारी करके सदन में आएं। मैं आपके द्वारा चाहता हूं कि प्रश्न को स्थगित करने का निर्देश दिया जाए और मंत्री जी पूरी तैयारी करने के बाद सदन में उत्तर दें।

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Mr. Raj Nath Singh, why are you interrupting me like this?

MR. CHAIRMAN: Mr. Singh, if you require more information, the Minister will supply it to you.

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Mr. Chairman, Sir, is the hon. Minister aware that the material given to the fair price shops is being diverted to private dealers? Since the prices of materials given to the fair price shops are low, the materials are being passed on to the private dealers by the fair price shop dealers. There are proceedings against such people under sections 5 and 6 of the Essential Commodities Act. A number of cases are there. A variety of such cases are taking place. Is the Minister aware that those materials are going into the free market?

श्री देवेन्द्र कुमार यादव: सभापति महोदय, आए दिन इस तरह की शिकायतें हमको मिली हैं। हमने माननीय मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों के समक्ष इसे रखा था कि राशन का डाएवर्शन हो जाता है। इस डाएवर्शन को रोकना राज्य सरकारों का काम है। फूड ग्रेन का मूमेंट, फूड ग्रेन का डाएवर्शन—यह राज्य सरकारों का काम है। परसों हमने एक गाइड लाइन केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को भेजी है कि इस तरह का डाएवर्शन नहीं होना चाहिए। इस पर कारगर कदम राज्य सरकार उठाए। वितरण करना राज्य सरकारों का काम है, हमारा काम स्टेट को ऐलोकेशन देना है।

MR. CHAIRMAN: Question No. 162— Shri Rahman Khan.

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Shrikant RamchandraJichkar.

*162. [*The questioner (Shri K. Rahman Khan) was absent. For answer, vide Col. 31 infra*]

Sick Industrial Units

*163. SHRI V. RAJESHWAR RAO:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:†

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the State-wise distribution of the sick industrial units as on the 1st July, 1996;

(b) the general reasons for this sickness;

(c) whether there are any state related specific reasons for this sickness; if so, the details thereof; and

(d) the steps being taken to control industrial sickness?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Data on sick industrial units assisted by Banks in the country is compiled by the Reserve Bank of India. According to the latest RBI data available, the state-wise distribution of sick industrial units, as at the end of March, 1995 is at Statement-I (*See* below).

(b) and (c) According to the RBI report, a number of causes, both internal and external, often operating in combination, have been responsible for industrial sickness. The main causes include deficiencies in planning, management, marketing, etc. The RBI report mentions change in Government policies as one of the external factors.

(d) The Government has taken a number of steps for revival of sick industrial units which, *inter-alia,* include,